

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

योगी सरकार का बड़ा कदम : उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति पर रोक, SP गुर्जर सम्मेलन 2027 रैली प्रभावित

Sanket Morankar

Published on 22 Sep 2025



उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीति और रैलियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। यह कदम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले का सीधा असर 2027 के SP गुर्जर सम्मेलन और उसकी रैलियों पर भी पड़ा है।

- योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, सभाओं और सम्मेलनों को रोकने का निर्णय लिया गया है।
- यह निर्णय सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
- सरकार ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी रैलियों और कार्यक्रमों को अनुमति न दी जाए।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा—

“हम चाहते हैं कि राजनीतिक गतिविधियाँ केवल लोकतांत्रिक और विकासपरक हों। जाति आधारित राजनीति समाज में विभाजन पैदा कर सकती है।”

- समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित गुर्जर सम्मेलन और रैली पर यह प्रतिबंध लागू हुआ।
- सम्मेलन के आयोजक और स्थानीय नेता इस फैसले से नाराजगी और चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

- राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम **राजनीतिक दलों की जाति आधारित रणनीति पर रोक** लगाने का संकेत है।

SP पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा—

“हमारा सम्मेलन समाज के विकास और समुदाय के हित में था, लेकिन सरकार ने इसे जाति आधारित राजनीति मान लिया। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे।”

- योगी सरकार के फैसले का समर्थन **कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों** ने किया।
- उनका कहना है कि यह निर्णय **समाज में सौहार्द बनाए रखने और अव्यवस्था रोकने** में मदद करेगा।
- वहीं, विपक्ष और SP समर्थक इसे **लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश** मान रहे हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से **उत्तर प्रदेश में जाति आधारित चुनावी रणनीति और राजनीतिक माहौल** प्रभावित होगा।

- राज्य सरकार ने कहा कि यह निर्णय **उत्तर प्रदेश स्थानीय प्रशासन अधिनियम और चुनाव आयोग की निर्देशावली** के तहत लिया गया है।
- अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई राजनीतिक दल इस नियम का उल्लंघन करता है, तो **सख्त कानूनी कार्रवाई** की जाएगी।
- वकीलों का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम **कानूनी ढांचे के भीतर** आयोजित करने की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि **2027 के विधानसभा चुनावों में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध** राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है।
- दलों को अब अपनी रणनीति **समुदाय और विकास आधारित मुद्दों** पर केंद्रित करनी होगी।
- यह कदम उत्तर प्रदेश में **राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द** बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।
- मीडिया और जनता में इस फैसले को लेकर **मिश्रित प्रतिक्रिया** देखने को मिली।
- कुछ लोग इसे **सकारात्मक और समाज सुधार के लिए जरूरी** मान रहे हैं।
- वहीं, अन्य लोग इसे **लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक** बताकर आलोचना कर रहे हैं।

एक स्थानीय नागरिक ने कहा—

“जाति आधारित राजनीति समाज में **मंतभेद बढ़ाती है**। सरकार का कदम सही दिशा में है।”

वहीं, एक राजनीतिक समर्थक ने कहा—

“हर दल अपने **वोट बैंक के लिए काम करता है**। पूरी तरह रोक देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डाल सकता है।”

योगी सरकार का यह कदम **जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक** लगाने और समाज में **सामाजिक सौहार्द बनाए रखने** की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

- SP गुर्जर सम्मेलन 2027 और अन्य राजनीतिक रैलियों पर इसका सीधा असर पड़ा है।

- राजनीतिक दल अब **समुदाय आधारित मुद्दों के बजाय विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे सामान्य मुद्दों** पर ध्यान देंगे ।
- जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि यह निर्णय **समाज में स्थिरता और सुरक्षा** बनाए रखने के लिए उठाया गया है ।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम उत्तर प्रदेश के **भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य** और आगामी विधानसभा चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.